Weekly One Liners 27th April to 3rd May, 2026

भारत और न्यूज़ीलैंड ने इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए साइन की ट्रेड डील

इंडिया-न्यूज़ीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में साइन किए गए। इस एग्रीमेंट पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल और न्यूज़ीलैंड के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर माननीय टॉड मैक्ले ने साइन किए। इस एग्रीमेंट को दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को मज़बूत करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा सकता है। इसका मकसद ट्रेड की रुकावटों को दूर करना, मार्केट एक्सेस को बेहतर बनाना और लंबे समय के आर्थिक मौके बनाना है।

100% ड्यूटी-फ्री एक्सेस से भारतीय एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला

इस एग्रीमेंट की खास बात यह है कि न्यूज़ीलैंड में 100% इंडियन एक्सपोर्ट के लिए ज़ीरो-ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब है कि न्यूज़ीलैंड के मार्केट में इंडियन सामान ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फ़ूड जैसे सेक्टर को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस एग्रीमेंट पर साइन होने से पहले इंडियन प्रोडक्ट्स पर 10% तक के टैरिफ़ ने उन्हें महंगा बना दिया था। अब MSMEs, कारीगरों और एक्सपोर्टर्स को बेहतर मौके मिलेंगे और इससे प्रोडक्शन, जॉब क्रिएशन और ग्लोबल ट्रेड पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

प्रमुख क्षेत्रों के संरक्षण के साथ संतुलित व्यापार

FTA एग्रीमेंट में भारत ने अपनी 70% टैरिफ लाइनें खोलकर शर्तों को ध्यान से बैलेंस किया है, साथ ही डेयरी, खेती और मेटल जैसे सेंसिटिव सेक्टर को भी बचाया है। लगभग 30% प्रोडक्ट्स से तुरंत ड्यूटी हटाई जाएगी, जबकि बाकी प्रोडक्ट्स पर कई सालों में धीरे-धीरे कटौती की जाएगी। साथ ही , सेब, कीवी और मनुका शहद जैसी चीज़ों पर टैरिफ रेट कोटा जैसे खास सेफगार्ड भी लागू किए गए हैं। इससे कंज्यूमर को फायदा होगा और साथ ही भारतीय किसानों और घरेलू इंडस्ट्रीज़ को अचानक होने वाले कॉम्पिटिशन से बचाया जा सकेगा।

सर्विसेज़ और स्किल्ड जॉब्स में बड़े मौके

FTA से सर्विसेज़ में बड़े फ़ायदे मिलेंगे , क्योंकि न्यूज़ीलैंड IT, एजुकेशन, फ़ाइनेंस और टूरिज़्म जैसे 118 सेक्टर खोल रहा है। साथ ही, इंडियन प्रोफ़ेशनल्स को नए वीज़ा पाथवे से फ़ायदा होगा, जिसमें 5,000 स्किल्ड वर्कर्स को तीन साल तक रहने की इजाज़त मिलेगी। यह योग इंस्ट्रक्टर, शेफ़, टीचर और हेल्थकेयर वर्कर्स को भी सपोर्ट करता है। साथ ही , स्टूडेंट्स को भी बेहतर मौके मिलते हैं और एडमिशन पर कोई लिमिट नहीं होती, पार्ट-टाइम काम करने का अधिकार मिलता है और करियर ग्रोथ के लिए पढ़ाई के बाद वर्क वीज़ा बढ़ाया जाता है।

निवेश में तेज़ी और बाज़ार तक तेज़ पहुँच

न्यूज़ीलैंड ने भारत में USD 20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने का वादा किया है और यह इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल सर्विसेज़ जैसे सेक्टर्स को सपोर्ट करेगा। यह एग्रीमेंट ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मानकर भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेज़ के लिए एक्सेस को भी आसान बनाएगा । इससे लागत कम होगी और अप्रूवल्स में तेज़ी आएगी। इस ट्रेड फैसिलिटेशन से तेज़ कस्टम्स क्लियरेंस, पेपरलेस सिस्टम और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर जैसे उपाय बिज़नेस के लिए एक्सपोर्ट को आसान और ज़्यादा एफिशिएंट बना देंगे।

कृषि, एमएसएमई और सांस्कृतिक सहयोग

यह एग्रीमेंट जॉइंट रिसर्च, बेहतर खेती के तरीकों से खेती की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ावा देगा और इससे सप्लाई चेन में सुधार होगा। MSMEs और स्टार्टअप्स को कम रुकावटों, इनोवेशन सपोर्ट और ग्लोबल वैल्यू चेन एक्सेस से फायदा होगा। एक खास बात यह है कि इसमें कल्चरल एक्सचेंज और पारंपरिक ज्ञान पर फोकस किया गया है, जिसमें AYUSH सिस्टम और क्रिएटिव इंडस्ट्री शामिल हैं। साथ ही, ऑर्गेनिक ट्रेड भी आपसी पहचान के स्टैंडर्ड के तहत बढ़ेगा और इससे चाय, चावल और मसालों जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट खुलेंगे।

भारत-न्यूजीलैंड व्यापार का मजबूत भविष्य

क्योंकि दोनों देशों के बीच बाइलेटरल ट्रेड पहले से ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इस FTA से ट्रेड वॉल्यूम, एक्सपोर्ट और रोज़गार में काफ़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इससे डेवलप्ड इकॉनमी के साथ भारत के रिश्ते मज़बूत होंगे और इसका ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क बढ़ेगा । साथ ही , गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु और पंजाब तक, पूरे भारत के राज्यों को बेहतर एक्सपोर्ट से फ़ायदा होने की संभावना है। कुल मिलाकर, यह एग्रीमेंट लंबे समय की इकॉनमिक ग्रोथ, इनोवेशन और ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए मज़बूत नींव बनाता है।

RBI ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया मिशन SAKSHAM

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 28 अप्रैल, 2026 को मिशन SAKSHAM लॉन्च किया है और इसका मकसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकिंग (UCB) सेक्टर को मज़बूत करना है। यह पहल बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए स्किल, गवर्नेंस और इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने पर फोकस करती है। इस मिशन में लगभग 1.4 लाख पार्टिसिपेंट शामिल होंगे और यह मिशन बोर्ड मेंबर, सीनियर मैनेजमेंट और टेक्निकल स्टाफ जैसे अलग-अलग खास स्टेकहोल्डर को टारगेट करेगा।

RBI का मिशन SAKSHAM क्या है?

मिशन SAKSHAM का मतलब है ' सहकारी बैंक क्षमता निर्माण' और इसे मिशन-मोड कैपेसिटी-बिल्डिंग पहल के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

इसका मकसद पूरे भारत में अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों में काम करने वाले लोगों की स्किल्स और काबिलियत को अपग्रेड करना भी है।

इस प्रोग्राम में इन-पर्सन ट्रेनिंग और ई-लर्निंग मॉड्यूल दोनों शामिल हैं, जिससे एक्सेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पक्की होती है।

RBI ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि यह पहल सिर्फ़ ट्रेनिंग के बारे में नहीं है, बल्कि यह इन बैंकों के काम करने के तरीके में लंबे समय का बदलाव लाने के बारे में भी है।

यह पहल UCBs के अम्ब्रेला ऑर्गनाइज़ेशन और अलग-अलग कोऑपरेटिव फेडरेशन समेत खास स्टेकहोल्डर्स के साथ कई राउंड की बातचीत के बाद बनाई गई थी, और यह भी पक्का किया गया कि यह सेक्टर के सामने आने वाली असली चुनौतियों को हल करे।

Adda247 LIVE CLASSES

Online LIVE Classes for SSC, Banking, Railways and Other Govt Exams

Live & Recorded Classes

PDF Notes & Study Material

Mock Tests & Practice Questions

Doubt Solving Sessions

- Expert Faculty with Interactive Classes
- Full Exam Syllabus Coverage + Mock Tests
- Courses Available in Hindi, English & Regional Languages

Get Started Now

इस पहल से किसे फ़ायदा होगा?

मिशन SAKSHAM की पहुंच बहुत बड़ी है और यह बैंकिंग सिस्टम के अंदर कई लेवल को टारगेट करेगा।

इसमें शामिल हैं,

- बोर्ड के सदस्य और निदेशक
- वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी
- जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा प्रमुख
- आईटी और तकनीकी कर्मचारी
- महत्वपूर्ण परिचालन भूमिकाओं में कर्मचारी

इस तरह के अलग-अलग तरह के ग्रुप को कवर करके RBI का मकसद यह पक्का करना है कि लीडरशिप और एग्ज़िक्यूशन, दोनों लेवल एक साथ बेहतर होंगे और इससे पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनल मज़बूती आएगी।

फोकस एरिया: स्किल्स, कम्प्लायंस और गवर्नेंस

मिशन SAKSHAM के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम UCB सेक्टर की कुछ सबसे ज़रूरी समस्याओं को हल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

मुख्य फोकस मैनेजरियल और ऑपरेशनल क्षमताओं को बेहतर बनाने पर है, जो अच्छी बैंकिंग सेवाओं के लिए ज़रूरी हैं।

इस पहल का मकसद कम्प्लायंस कल्चर को मज़बूत करना और यह पक्का करना भी है कि बैंक रेगुलेटरी नियमों का ज़्यादा अच्छे से पालन करें।

एक और ज़रूरी बात है रिस्क मैनेजमेंट और ऑडिट प्रैक्टिस को बेहतर बनाना, जिससे फाइनेंशियल गड़बड़ियों को रोकने और ट्रांसपेरेंसी सुधारने में मदद मिलेगी।

RBI ने रीजनल भाषा की ट्रेनिंग के महत्व पर भी ज़ोर दिया है और इस प्रोग्राम को भारत के अलग-अलग हिस्सों में कई इंस्टीट्यूशन के लिए इनक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाने पर भी ज़ोर दिया है।

शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने की ज़रूरत क्यों है?

अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक भारत के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में और खासकर छोटे बिज़नेस, लोकल कम्युनिटी और मिडिल-इनकम ग्रुप को बैंकिंग सर्विस देने में अहम भूमिका निभाते हैं।

हालाँकि, इस सेक्टर को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है,

- कमज़ोर गवर्नेंस स्ट्रक्चर।
- सीमित प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़।
- कुछ कम्प्लायंस गैप्स।
- टेक्नोलॉजिकल सीमाएं।

मिशन SAKSHAM का मकसद सिस्टम के अंदर ज्ञान, स्किल्स और अकाउंटेबिलिटी की मज़बूत नींव बनाकर इन समस्याओं को हल करना भी है।

सतत शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के उलट, मिशन SAKSHAM को लगातार सीखने का सेल्फ-सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

RBI एक ऐसे सिस्टम की भी कल्पना करता है, जिसमें ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट एक बार की कोशिश के बजाय एक लगातार चलने वाला प्रोसेस बन जाए।

इससे UCBs को बदलते फाइनेंशियल रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी में तरक्की और मार्केट की मांगों के हिसाब से ढलने में मदद मिलेगी।

आखिर में इस मिशन से को-ऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की सिस्टमिक स्टेबिलिटी और लॉन्ग-टर्म ग्रोथ में योगदान की उम्मीद की जाएगी।

राष्ट्रीय समाचार

- भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाईवे पर सुरक्षित यात्रा आर्टिकल 21 (जीवन का अधिकार) के तहत एक बुनियादी अधिकार है , जो इसके दायरे को सिर्फ़ ज़िंदा रहने से आगे बढ़ाकर सुरक्षित आने-जाने तक ले जाता है। इस फैसले में राज्य को सड़क सुरक्षा में सुधार करने , सड़क किनारे बने ढाबों जैसे गैर-कानूनी ढांचों को हटाने और गाड़ी पार्किंग को रेगुलेट करने का आदेश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि नेशनल हाईवे , हालांकि सड़कों का सिर्फ़ 2% हैं, लेकिन लगभग 30% मौतें इन्हीं पर होती हैं। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स बनाने का भी निर्देश दिया। यह ऐतिहासिक फैसला नागरिकों की सुरक्षा को मज़बूत करता है , जवाबदेही सुनिश्चित करता है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और टाले जा सकने वाले सड़क हादसों को रोकता है।
- नीति आयोग ने भारत को $18,000 प्रति व्यक्ति आय के साथ $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए DPI@2047 रोडमैप लॉन्च किया। इस प्लान में डिजिटल एम्पावरमेंट और इनक्लूसिव एक्सेस पर फोकस करने वाला DPI 2.0 (2025–2035) और इनोवेशन-लेड ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला DPI 3.0 (2035–2047) शामिल है। आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसे प्लेटफॉर्म पर आधारित , यह MSMEs , कृषि , शिक्षा और हेल्थकेयर को टारगेट करता है । यह पहल फाइनेंशियल इनक्लूजन , जॉब क्रिएशन को सपोर्ट करती है, और सस्टेनेबल और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लक्ष्य के साथ विकसित भारत 2047 के साथ अलाइन है।
- इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने नई दिल्ली से 14 दिन का भारत-भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर शुरू किया है , जिसमें भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन के ज़रिए प्रीमियम रेल-कम-रोड यात्रा की सुविधा है। पूर्वोत्तर भारत और भूटान को कवर करते हुए , मुख्य जगहों में गुवाहाटी, शिलांग, थिम्पू और पारो शामिल हैं। पैकेज में लग्ज़री केबिन , खाना , 3-स्टार स्टे और गाइडेड साइटसीइंग शामिल हैं। इसकी कीमत ₹ 1.16 लाख से शुरू होती है और यह एक परेशानी-मुक्त यात्रा अनुभव सुनिश्चित करता है। यह पहल टूरिज्म को बढ़ावा देती है , भारत-भूटान कनेक्टिविटी को मज़बूत करती है और चुनी हुई यात्रा के ज़रिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है।
- एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पीलीभीत में ₹ 15 करोड़ का बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाएगी। यह सेंटर किसानों को बासमती की खेती , ऑर्गेनिक खेती और एक्सपोर्ट के तरीकों की ट्रेनिंग देगा , जिसे AI-बेस्ड क्रॉप मैपिंग और क्वालिटी टेस्टिंग के लिए NABL-एक्रेडिटेड लैब से सपोर्ट मिलेगा। 50,000 से ज़्यादा किसानों को टारगेट करते हुए, यह प्रोडक्टिविटी , ट्रेसेबिलिटी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा । यह पहल भारत के एग्री -एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मज़बूत करती है , हाई-वैल्यू फसलों को बढ़ावा देती है , और किसानों को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्किल्स से मज़बूत बनाती है।

- 30 अप्रैल को मनाया जाने वाला आयुष्मान भारत दिवस , 2018 में शुरू की गई भारत की सबसे बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जश्न मनाता है। यह हर परिवार को ₹ 5 लाख तक का कैशलेस हेल्थकेयर कवरेज देता है , जिससे 10.74 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को फ़ायदा होता है । यह पहल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पक्का करती है , जिसमें 1,900+ इलाज , देश भर में पोर्टेबिलिटी और पहले से मौजूद बीमारियों का कवरेज मिलता है । यह मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर ग्रुप को सपोर्ट करता है, जिससे फ़ाइनेंशियल बोझ कम होता है और हेल्थकेयर तक पहुँच बेहतर होती है। ग्लोबल हेल्थ लक्ष्यों के साथ मिलकर, यह स्कीम भारत के पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मज़बूत करती है , हेल्थ इक्विटी को बढ़ावा देती है और "सभी के लिए हेल्थकेयर" की ओर बढ़ती है।
- नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 594 km लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया , जिसे ₹ 36,230 करोड़ की लागत से बनाया गया है , ताकि कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके । मेरठ को प्रयागराज से 12 जिलों से जोड़ने वाला, छह लेन (आठ तक बढ़ाया जा सकने वाला) कॉरिडोर यात्रा के समय को 10-12 घंटे से घटाकर लगभग 6 घंटे कर देता है । इसकी एक खास बात डिफेंस में इस्तेमाल के लिए 3.5 km की इमरजेंसी एयरस्ट्रिप है। यह प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को बढ़ाएगा , इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सपोर्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेगा, जिससे उत्तर प्रदेश ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और रीजनल डेवलपमेंट का एक बड़ा हब बन जाएगा ।
- पंचायती राज मंत्रालय ने नेशनल पंचायती राज डे पर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI) 2.0 रिपोर्ट जारी की , जिसमें ग्रामीण विकास में हुई प्रगति दिखाई गई है । कुल 3,635 ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर (A ग्रेड) के तौर पर उभरीं , जिसमें 2.59 लाख से ज़्यादा पंचायतों की 97.3% भागीदारी थी । रिपोर्ट में आजीविका , स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करने वाले 150 इंडिकेटर्स पर गवर्नेंस का मूल्यांकन किया गया है। गरीबी कम करने और स्वास्थ्य सुधार में अच्छा प्रदर्शन देखा गया । बेहतर डेटा ट्रांसपेरेंसी , रियल-टाइम मॉनिटरिंग और ग्राम सभा वैलिडेशन के साथ , PAI 2.0 जमीनी स्तर पर गवर्नेंस को मजबूत करता है और ग्रामीण विकास की लक्षित पहलों को सपोर्ट करता है।
- भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के तहत जून से अगस्त तक होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 की घोषणा की है , जिससे बॉर्डर पार तीर्थयात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। भक्त लिपुलेख पास (ट्रेक-बेस्ड) और नाथू ला पास (गाड़ी के लिए आसान) से यात्रा करेंगे। इस यात्रा में 50 तीर्थयात्रियों के 20 बैच (कुल 1,000) शामिल हैं , जिन्हें डिजिटल रैंडम प्रोसेस से चुना गया है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास होने वाली यह यात्रा हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए बहुत महत्व रखती है , जो आध्यात्मिक शुद्धि और भक्ति का प्रतीक है।
- 2 मई, 2026 को नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) की लीडरशिप में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का पूरे देश में ट्रायल किया , जिसमें सुबह 11:42 AM पर टेस्ट अलर्ट भेजे गए । यह सिस्टम भूकंप, बाढ़ और साइक्लोन जैसी आपदाओं के दौरान , फ़ोन नंबर पर निर्भर हुए बिना, रियल-टाइम, लोकेशन-बेस्ड इमरजेंसी वॉर्निंग देता है। C-DOT के बनाए SACHET इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम से पावर्ड , यह 19+ भाषाओं को सपोर्ट करता है और नेटवर्क कंजेशन के दौरान भी काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स के साथ मिलकर बनाया गया , यह आपदा की तैयारी, तेज़ी से कम्युनिकेशन और पब्लिक सेफ्टी को बढ़ाता है , जिससे यह पक्का होता है कि प्रभावित इलाकों के सभी मोबाइल यूज़र्स तक समय पर अलर्ट पहुँचें।
- लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 2026-27 (1 मई-30 अप्रैल) के लिए चार खास पार्लियामेंट्री कमेटियों को फिर से बनाया है। इनमें एस्टिमेट्स कमिटी (संजय जायसवाल) , पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (केसी वेणुगोपाल) , पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी (बैजयंत पांडा) , और SC/ST के वेलफेयर कमिटी (फग्गन सिंह कुलस्ते) शामिल हैं । ये कमेटियां सरकारी खर्च, PSU परफॉर्मेंस और वेलफेयर पॉलिसी का रिव्यू करके फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सोशल जस्टिस पक्का करती हैं। संविधान के आर्टिकल 105 और 118 के तहत , ये कमेटियां भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, चेक्स एंड बैलेंस और असरदार गवर्नेंस को मजबूत करती हैं ।
- भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के ज़रिए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को नोटिफ़ाई किया है , जो नागरिकता नियम, 2009 को अपडेट करते हैं । मुख्य बदलावों में OCI और नागरिकता एप्लीकेशन का पूरा डिजिटलाइज़ेशन , e-OCI (डिजिटल रजिस्ट्रेशन) की शुरुआत , और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत को हटाना शामिल है। इसमें साफ़ किया गया है कि नाबालिग भारतीय और विदेशी दोनों पासपोर्ट नहीं रख सकते । OCI छोड़ने के लिए अब ऑनलाइन डिक्लेरेशन और कार्ड सरेंडर करना होगा। एप्लीकेंट को फ़ास्ट-ट्रैक इमिग्रेशन के लिए बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन के लिए भी मंज़ूरी देनी होगी। इन सुधारों का मकसद भारत के नागरिकता और इमिग्रेशन सिस्टम में एफ़िशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, कम्प्लायंस, और प्रोसेसिंग में आसानी को बढ़ाना है।

राज्य समाचार

- जस्टिस लिसा गिल ने विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली , जो भारत की ज्यूडिशियरी में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है । शपथ गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर ने दिलाई । उनकी नियुक्ति लीगल सिस्टम में जेंडर इक्वालिटी , इनक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी की दिशा में हुई प्रोग्रेस को दिखाती है । मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बधाई दी। यह ऐतिहासिक कदम लीगल प्रोफेशन में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी को बढ़ावा देता है और भारत के ज्यूडिशियल इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को मज़बूत करता है ।
- एन चंद्रबाबू नायडू की लीडरशिप वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य को भारत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनाने के लिए ₹ 13,000 करोड़ का मशरूम मिशन शुरू किया । 67,500 टन प्रोडक्शन और 1.62 लाख यूनिट्स का टारगेट रखते हुए , यह छोटे किसानों , सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) और गांव के रोज़गार पर फोकस करता है। 40% सब्सिडी सपोर्ट के साथ , यह पहल मिल्की , पैडी स्ट्रॉ और बटन मशरूम जैसी वैरायटी को बढ़ावा देती है। इसका मकसद एक मजबूत एग्री वैल्यू चेन बनाना , एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और सस्टेनेबल इनकम जेनरेट करना है, जिससे राज्य एग्री -बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप और गांव के डेवलपमेंट का हब बन सके।

- लद्दाख को पांच नए जिले मिलेंगे — नुब्रा, शाम, चांगथांग, ज़ांस्कर और द्रास — जिससे कुल जिले 2 से बढ़कर 7 हो जाएंगे, जिससे डिसेंट्रलाइज़्ड गवर्नेंस और रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। वीके सक्सेना की लीडरशिप में अनाउंस किए गए इस कदम का मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में सुधार करना, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बढ़ाना और लंबे समय से चली आ रही लोकल डिमांड को पूरा करना है। इससे इकोनॉमिक मौके बनने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने और दूर-दराज के समुदायों को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। आर्टिकल 370 हटने के बाद के रिफॉर्म्स से जुड़ा यह कदम बॉर्डर इलाकों में इनक्लूसिव गवर्नेंस और बैलेंस्ड डेवलपमेंट को मजबूत करता है।
- भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद अब तक का सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, हाल के विधानसभा चुनावों में कुल 92.47% वोटिंग हुई। पहले चरण में 93.19% वोटिंग हुई, जबकि दूसरे चरण में 91.66% वोटिंग हुई, जो पिछले 84.72% (2011) के रिकॉर्ड को पार कर गया। खास बात यह है कि महिला वोटरों (92.28%) ने पुरुष वोटरों (91.07%) को पीछे छोड़ दिया, जो बढ़ती जेंडर इनक्लूसिविटी और डेमोक्रेटिक जुड़ाव को दिखाता है। यह ऐतिहासिक भागीदारी चुनावों में जनता के मज़बूत भरोसे, वोटरों की बढ़ती जागरूकता और भारत की डेमोक्रेटिक प्रक्रिया की मज़बूती को दिखाती है।
- बेंगलुरु पुलिस ने नम्मा 112 हेल्पलाइन में AI-पावर्ड मल्टीलिंगुअल फीचर शुरू किया है, जिससे बंगाली, मलयालम, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी जैसी 10+ भारतीय और विदेशी भाषाओं में बातचीत हो सकेगी। वॉइस AI टेक्नोलॉजी पर बना यह सिस्टम रियल-टाइम ट्रांसलेशन पक्का करता है, जिससे इमरजेंसी के दौरान देरी कम होती है। रोज़ाना लगभग 8,000 कॉल्स के साथ, जिसमें 100-200 भाषा की दिक्कत वाले मामले शामिल हैं, यह सिस्टम इमरजेंसी में जवाब देने की क्षमता और एक्सेस को बेहतर बनाता है। यह पब्लिक सेफ्टी को मज़बूत करता है, इंटरनेशनल विज़िटर्स को सपोर्ट करता है, और बेंगलुरु जैसे दुनिया भर में अलग-अलग तरह के शहर में डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट पुलिसिंग और सबको साथ लेकर चलने वाली इमरजेंसी सर्विस की तरफ भारत के कदम को दिखाता है।
- कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए भारत का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम लॉन्च किया है, जिसे कर्नाटक प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स बोर्ड ने ई-गवर्नेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बनाया है। इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम (IPGRS) के ज़रिए, वर्कर्स सैलरी, इंसेंटिव और काम करने के हालात से जुड़े मामलों की रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें रियल-टाइम ट्रैकिंग और टाइम-बाउंड सॉल्यूशन शामिल है। यह पहल वर्कर्स, प्लेटफॉर्म और अधिकारियों के बीच एक फॉर्मल लिंक बनाती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और वर्कर प्रोटेक्शन बढ़ता है। यह गिग इकॉनमी को रेगुलेट करने और डिलीवरी पार्टनर और राइड-हेलिंग ड्राइवर जैसे ऐप-बेस्ड वर्कर्स के अधिकार पक्का करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

- भारत ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के ज़रिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के सपोर्ट से पांच साल का बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट (2025–2030) शुरू किया है। तमिलनाडु और मेघालय पर फोकस करते हुए, यह ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (GPDPs) में बायोडायवर्सिटी को जोड़कर ज़मीनी स्तर पर शासन को मज़बूत करता है। यह पहल कम्युनिटी की भागीदारी, सस्टेनेबल आजीविका और इको-फ्रेंडली उद्यमों को बढ़ावा देती है। यह PRIs और BMCs जैसे संस्थानों को सपोर्ट करता है, एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग (ABS) पक्का करता है, और महिलाओं और आदिवासी समुदायों को मज़बूत बनाता है, बायोडायवर्सिटी संरक्षण और स्थानीय विकास को बढ़ाता है।
- वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ने वर्ल्ड मलेरिया डे 2026 पर बच्चों के लिए खास मलेरिया की पहली दवा को मंज़ूरी दी, जिसका टारगेट 5 kg से कम वज़न वाले बच्चे हैं। आर्टीमीथर -ल्यूमेफैंट्रिन फ़ॉर्मूलेशन सेफ़ डोज़ पक्का करता है, टॉक्सिसिटी का खतरा कम करता है और बच्चों की देखभाल को बेहतर बनाता है। यह माइलस्टोन दुनिया भर में तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूशन को मुमकिन बनाता है, खासकर सब-सहारा अफ्रीका जैसे मलेरिया से फैलने वाले इलाकों में, जहाँ 90% मामले होते हैं। पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की वजह से मलेरिया से होने वाली मौतों में लगभग 70% हिस्सा होता है, इसलिए यह दवा ज़रूरी सुरक्षा देती है। माँ और बच्चे की हेल्थ को सपोर्ट करते हुए, यह इनोवेशन मलेरिया से लड़ने, बचने की दर को बेहतर बनाने और सभी तक हेल्थकेयर की पहुँच को बेहतर बनाने की दुनिया भर की कोशिशों को मज़बूत करता है।
- इमैनुएल मैक्रों ने ऐलान किया कि वह 2027 के बाद पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, और फ्रांस के प्रेसिडेंट के तौर पर अपना दूसरा टर्म पूरा करेंगे। निकोसिया में बोलते हुए, उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल वापसी से इनकार किया, जिससे अटकलों पर विराम लग गया। 2017 में सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट के तौर पर पहली बार चुने गए और 2022 में फिर से चुने गए, उनके कार्यकाल में बड़े सुधार हुए, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करना शामिल था, साथ ही पब्लिक प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल चैलेंज भी हुए। फ्रांस की दो-टर्म की लिमिट के साथ, उनका यह फैसला लीडरशिप में बदलाव का संकेत देता है, जो एक अहम पॉलिटिकल युग के खत्म होने और देश के भविष्य के पॉलिटिकल माहौल को आकार देने का संकेत है।
- यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट एनालेना बेयरबॉक 28 अप्रैल, 2026 को भारत आएंगी, जो इस रोल में उनकी पहली ट्रिप होगी। इस विज़िट में ग्लोबल कोऑपरेशन, मल्टीलेटरलिज़्म और क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन जैसी चुनौतियों से निपटने पर फोकस किया जाएगा। वह एस. जयशंकर और दूसरे अधिकारियों के साथ डिजिटल गवर्नेंस और UN कोऑपरेशन पर बातचीत करेंगी। यह विज़िट ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत की बढ़ती भूमिका को हाईलाइट करती है, जिसके बाद वह चीन में अपनी अगली मीटिंग करेंगी, जिससे इंटरनेशनल पार्टनरशिप मजबूत होगी।
- सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने UNESCO के साथ मिलकर जेंडर इन्क्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया का पहला UNESCO चेयर लॉन्च किया। इस पहल का मकसद AI, रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी को बढ़ावा देकर महिलाओं को मजबूत बनाना है। जयंत चौधरी ने इसका उद्घाटन किया, यह भविष्य के स्किल्स, जेंडर इक्वालिटी और रोजगार के मौकों पर फोकस करता है। 10,000 से ज़्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग देने के साथ, यह ग्लोबल फर्मों को शामिल करते हुए इंडस्ट्री-एकेडेमिया के बीच मजबूत सहयोग को दिखाता है। यह मील का पत्थर जेंडर गैप को कम करने और उभरते उद्योगों के लिए समावेशी स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।

- भारत ने 2031-2035 के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत किया, जिसमें 47% उत्सर्जन तीव्रता में कमी , 60% गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और 3.5-4 बिलियन टन कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा गया है। पेरिस समझौते के अनुरूप , यह योजना स्वच्छ ऊर्जा , वन विस्तार और हरित विकास पर जोर देती है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के समर्थन से , भारत वैश्विक जलवायु कार्रवाई में अपनी भूमिका को मजबूत करता है, विकास और स्थिरता को संतुलित करते हुए अपने 2070 नेट-जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ता है।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार , 2025 में भारत पाँचवाँ सबसे बड़ा मिलिट्री खर्च करने वाला देश बन जाएगा , जिसका खर्च बढ़कर $92.1 बिलियन हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन , बॉर्डर सिक्योरिटी और भारत-पाकिस्तान विवाद समेत क्षेत्रीय तनावों की वजह से डिफेंस खर्च 8.9% बढ़ा। भारत अब US, चीन, रूस और जर्मनी से पीछे है , जो बढ़ते ग्लोबल मिलिट्री खर्च में योगदान दे रहे हैं। एयरक्राफ्ट , मिसाइल और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में बढ़ा हुआ इन्वेस्टमेंट डिफेंस की तैयारी पर इसके फोकस को दिखाता है । यह ट्रेंड ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने और एक मजबूत मिलिट्री क्षमता बनाए रखने की दिशा में भारत के स्ट्रेटेजिक प्रयास को दिखाता है ।
- यूनाइटेड अरब अमीरात ने 1 मई, 2026 से ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ से बाहर निकलने का ऐलान किया , जिससे लगभग 60 साल की मेंबरशिप खत्म हो गई। इस कदम का मकसद ज़्यादा प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी पाना और OPEC कोटा से ज़्यादा आउटपुट बढ़ाना है। एनालिस्ट प्रोडक्शन लिमिट से नाखुशी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की मांग पर ध्यान दे रहे हैं । इस फैसले से OPEC का असर कम हो सकता है और ग्लोबल तेल सप्लाई बढ़ सकती है , जिससे कीमतें कम हो सकती हैं लेकिन मार्केट में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। होर्मुज स्ट्रेट में रुकावटों सहित जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच, यह बदलाव ग्लोबल एनर्जी डायनामिक्स में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है ।
- फ़िनलैंड ने कोक्कोला के पास यूरोप का पहला पूरी तरह से इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट लॉन्च किया , जिसमें माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग तक शामिल है। केलिबर प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर , इसका मकसद हर साल 15,000 टन लिथियम हाइड्रॉक्साइड बनाना है , जो इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बैटरी और क्लीन एनर्जी स्टोरेज को सपोर्ट करेगा। सिबान्ये-स्टिलवॉटर जैसी फर्मों के सपोर्ट से , यह पहल यूरोप की एनर्जी इंडिपेंडेंस को मज़बूत करती है और इम्पोर्ट पर डिपेंडेंस कम करती है। लिथियम, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए एक ज़रूरी रिसोर्स है, यूरोप को ग्लोबल ग्रीन ट्रांज़िशन और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक मज़बूत प्लेयर के तौर पर खड़ा करता है ।
- फेडरल रिजर्व ने 29 अप्रैल, 2026 को इंटरेस्ट रेट्स को 3.50%–3.75% पर बिना किसी बदलाव के रखा , जो मिले-जुले आर्थिक हालात के बीच पॉलिसी में अनिश्चितता का संकेत है। इस फैसले में 8–4 का बंटवारा हुआ वोट देखने को मिला, जो महंगाई कंट्रोल बनाम आर्थिक ग्रोथ पर मतभेदों को दिखाता है । दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतें और जियोपॉलिटिकल तनाव महंगाई के दबाव को बढ़ा रहे हैं , जबकि लेबर मार्केट स्थिर बना हुआ है। कुछ पॉलिसीमेकर्स ने रेट में कटौती का समर्थन किया, जिससे भविष्य की दिशा में अनिश्चितता का पता चलता है। जेरोम पॉवेल का कार्यकाल खत्म होने वाला है और केविन वार्श के सफल होने की संभावना है, इसलिए US मॉनेटरी पॉलिसी का आउटलुक अनिश्चित बना हुआ है।
- भारत ने अपने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ (HADR) फ्रेमवर्क के तहत जमैका में आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थकेयर सिस्टम शुरू किया है, जो दुनिया भर में ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच में एक बड़ा कदम है। विदेश मंत्रालय और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट द्वारा कोऑर्डिनेट की गई यह पहल आपदा की स्थितियों में तेज़ी से, टेक्नोलॉजी से चलने वाली मेडिकल मदद देती है। यह CARICOM देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करता है और एक भरोसेमंद ग्लोबल हेल्थकेयर पार्टनर के तौर पर भारत की भूमिका को दिखाता है , जो आपदा से निपटने, हेल्थकेयर में सहयोग और कमज़ोर इलाकों में कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देता है ।

बैंकिंग/अर्थव्यवस्था/व्यापार समाचार

- सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ने एक प्रस्ताव दिया है ऑर्गनॉन एंड कंपनी का $11.75 बिलियन में एक्विजिशन , भारत की सबसे बड़ी विदेशी डील्स में से एक है । यह ऑल-कैश ट्रांज़ैक्शन, जो 2027 तक होने की उम्मीद है, सन फार्मा की 150 देशों में मौजूदगी बढ़ाएगा । ऑर्गनॉन के 70+ प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो और महिलाओं के हेल्थ और बायोसिमिलर्स पर फोकस भविष्य की ग्रोथ को मज़बूत करेगा। कंबाइंड एंटिटी $12.4 बिलियन का रेवेन्यू हासिल कर सकती है , जिससे यह टॉप ग्लोबल फार्मा कंपनियों में शामिल हो जाएगी। यह स्ट्रेटेजिक कदम ग्लोबल हेल्थकेयर मार्केट्स में भारत की पोजीशन को मज़बूत करता है और बायोसिमिलर्स के ज़रिए सस्ती दवाओं को बढ़ावा देता है।
- वन मोबिक्विक सिस्टम्स को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से NBFC अप्रूवल मिला , जिससे रेगुलेटेड डिजिटल लेंडिंग स्पेस में एंट्री हो गई । कंपनी लोन देने और अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए मोबिक्विक फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च करेगी। 18.6 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स और मज़बूत टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ , यह कदम पेमेंट से पूरी तरह फाइनेंशियल सर्विसेज़ की ओर एक बदलाव दिखाता है । यह अप्रूवल क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, फाइनेंशियल इनक्लूजन को सपोर्ट करता है , और भारत के फिनटेक इकोसिस्टम को मज़बूत करता है, खासकर कम सर्विस वाले सेगमेंट तक क्रेडिट एक्सेस बढ़ाने में।
- वीज़ा इंक. ने सुरेश सेठी को इंडिया और साउथ एशिया के लिए ग्रुप कंट्री मैनेजर अपॉइंट किया है , जिसका मकसद डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल इनोवेशन को बढ़ावा देना है। मुंबई में रहने वाले सेठी इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान में ऑपरेशन्स देखेंगे । सेठी संदीप घोष की जगह लेंगे और प्रोटीन ई-गॉव टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड से अनुभव लेकर आए हैं , जहाँ उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को आगे बढ़ाया था। उनकी लीडरशिप वीज़ा के फिनटेक इनोवेशन , फाइनेंशियल इनक्लूजन को बढ़ाने और साउथ एशिया में डिजिटल इकॉनमी को मजबूत करने के विज़न से मेल खाती है।

- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बड़े पैमाने पर कैपेसिटी बिल्डिंग के ज़रिए अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों (UCBs) को मज़बूत करने के लिए मिशन SAKSHAM (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण) लॉन्च किया है। इस पहल में बोर्ड मेंबर्स , सीनियर मैनेजमेंट और टेक्निकल स्टाफ़ समेत लगभग 1.4 लाख पार्टिसिपेंट्स को ई-लर्निंग और ऑफ़लाइन प्रोग्राम्स के ज़रिए ट्रेनिंग दी जाएगी । यह गवर्नेंस , रिस्क मैनेजमेंट , कम्प्लायंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने पर फ़ोकस करता है। कमज़ोर गवर्नेंस और स्किल गैप जैसे मुद्दों को हल करते हुए, इस मिशन का मकसद फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है। यह कदम UCB सेक्टर को मॉडर्नाइज़ करने और लोकल कम्युनिटीज़ और छोटे बिज़नेस के लिए बैंकिंग सर्विसेज़ को बेहतर बनाने के RBI के कमिटमेंट को मज़बूत करता है।
- पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के दौरान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) फीस में 3 साल की छूट की घोषणा की , जिसका मकसद स्पोर्ट्स इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इस छूट में पेटेंट , ट्रेडमार्क , कॉपीराइट और GI टैग शामिल हैं , जिससे स्टार्टअप , एथलीट और स्टूडेंट्स को अपने आइडिया को बचाने के लिए बढ़ावा मिलेगा। यह पहल "इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस, प्रॉस्पर" को सपोर्ट करती है और कश्मीर विलो बैट जैसे प्रोडक्ट्स पर ज़ोर देती है । प्लान्स में स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और IIT दिल्ली के साथ एक वियरेबल्स हैकाथॉन शामिल है, जिससे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और भारत की स्पोर्ट्स इकोनॉमी मज़बूत होगी।
- नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार , मार्च 2026 में भारत का इंडस्ट्रियल आउटपुट (IIP) ग्रोथ घटकर 4.1% रह गया, जो पिछले पांच महीनों में सबसे कम है। यह गिरावट मैन्युफैक्चरिंग (4.3%) और पावर सेक्टर (0.8%) के कमजोर परफॉर्मेंस की वजह से हुई , जबकि माइनिंग ने 5.5% ग्रोथ के साथ मजबूती दिखाई । इंडेक्स ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को दिखाता है , और यह मंदी कमजोर डिमांड और सेक्टर की चुनौतियों का संकेत देती है। इसके बावजूद, सालाना ग्रोथ 4.1% पर स्थिर रही , जो मामूली लेकिन असमान इंडस्ट्रियल रिकवरी को दिखाता है और खास सेक्टर में मजबूत मोमेंटम की ज़रूरत को दिखाता है।
- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने आपदा प्रभावित इलाकों के लिए नई लोन रीस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस जारी की हैं, जो 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगी । बैंक और NBFC अब बिना कर्जदार के रिक्वेस्ट के लोन को प्रोएक्टिवली रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जिससे तेज़ी से फाइनेंशियल राहत मिलेगी । रिस्क और स्टेबिलिटी को बैलेंस करने के लिए 5% प्रोविजनिंग नॉर्म ज़रूरी है। सिर्फ़ स्टैंडर्ड अकाउंट (≤30 दिन ओवरड्यू) ही एलिजिबल हैं, जिसमें कर्जदारों के लिए 135-दिन का ऑप्ट-आउट ऑप्शन है। फ्रेमवर्क के लिए 45 दिनों के अंदर एक्शन और 90 दिनों में पूरा करना ज़रूरी है । यह कदम फाइनेंशियल रेजिलिएंस को मज़बूत करता है , प्रभावित कर्जदारों को सपोर्ट करता है, और बैंकिंग सिस्टम की क्राइसिस रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को बढ़ाता है।
- एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन, बिना UAN वाले डॉर्मेंट PF अकाउंट को ट्रेस करने और रीएक्टिवेट करने में यूज़र्स की मदद के लिए E-PRAAPTI पोर्टल लॉन्च करेगा । मनसुख मंडाविया द्वारा अनाउंस किया गया यह प्लेटफॉर्म सिक्योर एक्सेस के लिए आधार-बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करता है और यूज़र्स को अकाउंट को इंडिपेंडेंटली मैनेज करने की सुविधा देता है। यह ट्रांसपेरेंसी , डिजिटल गवर्नेंस और यूज़र एम्पावरमेंट को बढ़ाता है , खासकर उन लोगों के लिए जो कई बार नौकरी बदलते हैं। बढ़ते डिजिटल क्लेम सेटलमेंट और तेज़ प्रोसेसिंग के साथ, यह इनिशिएटिव EPFO के मॉडर्नाइज़ेशन की कोशिशों को मज़बूत करता है, जिससे लाखों सब्सक्राइबर्स के लिए एफिशिएंट, एक्सेसिबल और पेपरलेस सर्विस पक्की होती हैं।
- सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया ने 4 मई, 2026 से PaRRVA (पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी) सिस्टम को चालू कर दिया है , जिससे मार्केट ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बढ़ेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया के सपोर्ट से CARE रेटिंग्स लिमिटेड इसे मैनेज करता है , यह इन्वेस्टमेंट एडवाइजर , रिसर्च एनालिस्ट और दूसरों के परफॉर्मेंस क्लेम को वेरिफाई करता है। यह प्लेटफॉर्म सही, स्टैंडर्ड डेटा पक्का करता है , गुमराह करने वाले क्लेम कम करता है और सोच-समझकर इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने में मदद करता है। यह पहल अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करती है , इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाती है और भारत के फाइनेंशियल इकोसिस्टम की क्रेडिबिलिटी को बेहतर बनाती है।
- भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस , जिसे 2016 में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के तहत नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया ने लॉन्च किया था , ने एक दशक पूरा कर लिया है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। ट्रांज़ैक्शन 2 करोड़ से बढ़कर 24,000+ करोड़ हो गए , जिनकी वैल्यू ₹ 314 लाख करोड़ तक पहुँच गई , जो भारत के डिजिटल पेमेंट में 85% और दुनिया भर में 49% का योगदान देता है। इसकी सफलता तुरंत ट्रांसफ़र, इंटरऑपरेबिलिटी, कम लागत और इस्तेमाल में आसानी में है। P2P और P2M पेमेंट के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला UPI, दुनिया भर में भी फैला, जिससे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इनक्लूजन में भारत की लीडरशिप मज़बूत हुई।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHGs) को मज़बूत बनाने के लिए ज़ीरो-बैलेंस SHG सेविंग्स अकाउंट शुरू किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ़ कम्युनिकेशंस के तहत घोषित इस पहल में कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है, शुरुआती डिपॉज़िट ज़ीरो है, और ₹ 2 लाख की लिमिट है, जिससे बैंकिंग आसान हो गई है। इसका मकसद फाइनेंशियल इनक्लूजन, बचत की आदतों और डिजिटल बैंकिंग एक्सेस को बढ़ावा देना है , साथ ही इनफॉर्मल क्रेडिट पर निर्भरता कम करना है। SHGs को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में जोड़कर , यह कदम पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण, ज़मीनी स्तर पर आर्थिक विकास और सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ को मज़बूत करता है।
- नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने FY 2025-26 में ₹ 4,364 करोड़ की रिकवरी करके मज़बूत रिकवरी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट दी , जिससे कुल रिकवरी ₹ 6,345 करोड़ हो गई। इसने ₹ 1.65 लाख करोड़ के करीब एक्सपोज़र वाले 33 स्ट्रेस्ड बॉरोअर अकाउंट हासिल किए हैं , और अपने ₹ 2 लाख करोड़ के टारगेट की ओर बढ़ रहा है। इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) के साथ और इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत काम करते हुए, NARCL NPA को हल करने , बैंक बैलेंस शीट को बेहतर बनाने और तेज़ और ज़्यादा कुशल एसेट रिकवरी को मुमकिन बनाकर क्रेडिट फ़्लो और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।

- भारत का गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) कलेक्शन अप्रैल 2026 में रिकॉर्ड ₹ 2.42 लाख करोड़ पर पहुँच गया , जिसमें साल-दर-साल 8.7% की बढ़ोतरी हुई — यह अब तक का सबसे ज़्यादा मंथली कलेक्शन है। यह बढ़ोतरी ज़्यादातर मज़बूत इम्पोर्ट ग्रोथ की वजह से हुई , जिसने ₹ 57,000 करोड़ (25.8% ज़्यादा) से ज़्यादा का योगदान दिया, और बिज़नेस द्वारा साल के आखिर में स्टॉक क्लियरेंस , जिससे टैक्स पेमेंट बढ़ा। घरेलू GST ₹ 1.85 लाख करोड़ (4.3% बढ़ोतरी) पर स्थिर रहा। रिफंड के बाद, नेट कलेक्शन ₹ 2.11 लाख करोड़ रहा । हालाँकि, बढ़ते रिफंड (19.3% ज़्यादा) , खासकर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से , मज़बूत रेवेन्यू परफॉर्मेंस के बावजूद पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है।
- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बताया कि मई 2023 में वापस लिए गए ₹ 2,000 के नोटों में से 98.47% बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं, जो करेंसी मैनेजमेंट में एक बड़ा मील का पत्थर है । कुल सर्कुलेशन ₹ 3.56 लाख करोड़ से घटकर ₹ 5,451 करोड़ (अप्रैल 2026) हो गया। यह वापसी डीमॉनेटाइज़ेशन नहीं थी — नोट लीगल टेंडर बने हुए हैं लेकिन अब एक्टिव रूप से सर्कुलेट नहीं होते हैं। RBI ऑफिस और बैंकों के ज़रिए आसान एक्सचेंज से कम से कम दिक्कत हुई। इस कदम का मकसद साफ़ करेंसी सर्कुलेशन को बढ़ावा देना , ज़्यादा कीमत वाले कैश का इस्तेमाल कम करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना था , जो भारत के ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और कुशल फाइनेंशियल सिस्टम की ओर बदलाव को दिखाता है।

नियुक्तियाँ/इस्तीफ़े

- दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड (DMIL) का पहला CEO बनाया है , जो ग्लोबल विस्तार की ओर एक कदम है। DMIL का मकसद कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के ज़रिए भारत की मेट्रो एक्सपर्टीज़ को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना है। जमुआर, जो पहले IRTS ऑफिसर थे, यूरोप और वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा ग्लोबल अनुभव लेकर आए हैं। DMRC, जो पहले से ही ढाका मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स में शामिल है , शहरी ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस में अपनी जगह मज़बूत करता है । यह कदम ग्लोबल मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल शहरी विकास में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है ।
- दिलीप कुमार ने 27 अप्रैल, 2026 को स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के चीफ़ विजिलेंस ऑफ़िसर (CVO) का पद संभाला । उनका मकसद PSU में ट्रांसपेरेंसी , अकाउंटेबिलिटी और विजिलेंस बढ़ाना है । इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ़ मैकेनिकल इंजीनियर्स के एक सीनियर ऑफ़िसर के तौर पर, उनके पास ऑपरेशन्स, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट में दो दशकों से ज़्यादा का अनुभव है। ISO-सर्टिफाइड ट्रेनों और व्हील रिप्लेसमेंट टेक्नीक जैसे इनोवेशन के लिए जाने जाने वाले , उनके पास IIT BHU से डिग्री है । उनकी नियुक्ति भारत के स्टील सेक्टर में गवर्नेंस और ऑपरेशनल इंटीग्रिटी को मज़बूत करती है ।
- इंडियन क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड ने भारत में F1 प्रोग्राम के लिए ब्रांड एंबेसडर बनाया है । इसके साथ ही, ईस्पोर्ट्स रेसिंग टैलेंट को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 लॉन्च किया गया है । इस पहल का मकसद गेमिंग और प्रोफेशनल मोटरस्पोर्ट को जोड़ना है , जिससे युवा खिलाड़ियों को एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा। अय्यर के शामिल होने से युवाओं की भागीदारी बढ़ने और मल्टी-स्पोर्ट इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो भारत में पारंपरिक खेलों, ईस्पोर्ट्स और डिजिटल इनोवेशन के बढ़ते मेल को दिखाता है।
- इंफोसिस ने नितिन परांजपे को नॉन -एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया है , जिससे कंपनी का गवर्नेंस और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप मजबूत होगा । बोर्ड से मंज़ूरी मिलने के बाद, वह चेयरमैन नंदन नीलेकणी के साथ मिलकर लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजी को गाइड करेंगे। परांजपे, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिज़नेस स्ट्रेटेजी में बहुत ज़्यादा ग्लोबल एक्सपीरियंस रखते हैं । यह रोल एडवाइजरी और बोर्ड-लेवल के फैसलों पर फोकस करता है, जिससे इंफोसिस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बदलते IT सेक्टर में ग्लोबल कॉम्पिटिशन में स्टेबिलिटी बनी रहे।
- विश्वजीत सहाय को रक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी (डिफेंस फाइनेंस) नियुक्त किया गया है , उनके पास डिफेंस फाइनेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है । 1990 बैच के IDAS ऑफिसर , उन्होंने पहले कंट्रोलर जनरल ऑफ़ डिफेंस अकाउंट्स (CGDA) के तौर पर काम किया था और कई मंत्रालयों में अहम भूमिकाएँ निभाई थीं। सेंट स्टीफंस कॉलेज से लॉ की डिग्री लेने वाले , उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जॉर्ज सी. मार्शल सेंटर से इंटरनेशनल अनुभव भी है । उनके अपॉइंटमेंट से भारत के डिफेंस सेक्टर में फाइनेंशियल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रेटेजिक फैसले लेने की क्षमता मज़बूत होने की उम्मीद है ।
- 1991 बैच के IDAS ऑफिसर अनुग्रह नारायण दास ने डिफेंस फाइनेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 30 साल से ज़्यादा के अनुभव के साथ कंट्रोलर जनरल ऑफ़ डिफेंस अकाउंट्स (CGDA) का पद संभाला है । वे उत्कल यूनिवर्सिटी के एल्युम्नस हैं , उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ़ लजुब्लजाना में इंटरनेशनल एक्सपोज़र और IIM बैंगलोर और ड्यूक यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग मिली है। उन्होंने एडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर (MoD) और प्रिंसिपल IFA, आर्मी हेडक्वार्टर जैसे अहम रोल निभाए हैं ।
- आशुतोष गोवारिकर को गोवा (नवंबर 2026) में होने वाले 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया 2026 के लिए फेस्टिवल डायरेक्टर बनाया गया है । 1984 से IFFI के साथ लंबे समय से जुड़े और पूर्व जूरी प्रेसिडेंट (2024) के साथ एक मशहूर फिल्ममेकर, वे अपने साथ मज़बूत क्रिएटिव विज़न और ग्लोबल अनुभव लेकर आए हैं । 1952 में शुरू हुआ IFFI एशिया के सबसे पुराने फिल्म फेस्टिवल में से एक है , जिसे मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, NFDC और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ़ गोवा ऑर्गनाइज़ करते हैं। 2026 एडिशन में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, मास्टरक्लास और रेट्रोस्पेक्टिव होंगे, जिसका मकसद ग्लोबल सिनेमैटिक कोलेबोरेशन और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना है ।
- 1995 बैच के IAS ऑफिसर भरत खेड़ा को मिनिस्ट्री ऑफ़ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) का सेक्रेटरी बनाया गया है । 30 साल से ज़्यादा के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के साथ , उनसे MSME सेक्टर को मज़बूत करने की उम्मीद है , जो भारत की GDP में 30% का योगदान देगा । उन्होंने पहले डिपार्टमेंट ऑफ़ कंज्यूमर अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया है , और मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेंस और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में अहम रोल निभाए हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी सीनियर पोस्ट पर काम किया है । BITS पिलानी , सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी और ISB के एल्युम्नस , वे MSME ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मज़बूत पॉलिसी, गवर्नेंस और लीडरशिप एक्सपर्टीज़ लाते हैं ।

रक्षा समाचार

- डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने अहिल्यानगर में दो एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किए , जिससे भारत की डिफेंस मजबूत होगी। मॉडर्नाइज़ेशन और सेल्फ-रिलाएंस। व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा डेवलप किए गए इन प्लेटफॉर्म्स में 30 mm क्रूलेस टरेट , 7.62 mm गन और एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGMs) के साथ ट्रैक्ड और व्हील्ड वेरिएंट शामिल हैं। हाई मोबिलिटी , STANAG लेवल 4/5 प्रोटेक्शन और मॉड्यूलर डिज़ाइन की खासियतों के साथ , ये अलग-अलग कॉम्बैट रोल्स के लिए सही हैं। 65% स्वदेशी कंटेंट (टारगेट 90%) और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और भारत फोर्ज लिमिटेड जैसी फर्मों के साथ कोलेबोरेशन के साथ, यह स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा कदम है।
- इंडियन आर्मी उमरोई फॉरेन ट्रेनिंग नोड में पहली एक्सरसाइज PRAGATI होस्ट करेगी , जिसमें 11 देश हिस्सा लेंगे। मिलिट्री कोऑपरेशन , इंटरऑपरेबिलिटी और आपसी भरोसे को बढ़ाने के मकसद से , यह एक्सरसाइज इंडियन ओशन रीजन में रीजनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया के कमिटमेंट को दिखाती है । PRAGATI (ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रीजनल आर्मीज़ की पार्टनरशिप) ASEAN और पड़ोसियों समेत पार्टनर देशों के बीच जॉइंट ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देती है । यह पहल डिफेंस संबंधों को मजबूत करती है, इंडिया के ग्लोबल मिलिट्री एंगेजमेंट को बढ़ाती है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में नॉर्थईस्ट रीजन के स्ट्रेटेजिक महत्व को हाईलाइट करती है।
- डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन और इंडियन नेवी ने नेवल एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज (NASM-SR) का पहला साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया , जिससे भारत की स्वदेशी डिफेंस क्षमताओं को बढ़ावा मिला। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में नेवल हेलीकॉप्टर से फायर की गई इस मिसाइल ने वॉटरलाइन स्ट्राइक क्षमता सहित सटीक निशाना लगाने का प्रदर्शन किया। एडवांस्ड नेविगेशन , टू-वे डेटा लिंक और हाई-प्रिसिजन सीकर से लैस , यह असरदार समुद्री युद्ध परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। मेक इन इंडिया के तहत विकसित, यह उपलब्धि भारत की नेवल स्ट्राइक पावर , टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता और पूरी समुद्री सुरक्षा तैयारी को मजबूत करती है।
- भारत और श्रीलंका ने कोलंबो में चौथा IN–SLN DIVEX 2026 किया , जिससे समुद्री सहयोग बढ़ा । इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी का जहाज INS निरीक्षक और श्रीलंका के गोताखोर शामिल थे, जो गहरे समुद्र में डाइविंग और मिक्स्ड-गैस ऑपरेशन पर फोकस कर रहे थे । इससे हिंद महासागर क्षेत्र में इंटरऑपरेबिलिटी , ऑपरेशनल तैयारी और समुद्री सुरक्षा में सुधार हुआ। ड्रिल के साथ-साथ, जॉइंट एक्सरसाइज , योग और आरोग्य मैत्री के तहत मानवीय मदद जैसी गतिविधियों ने द्विपक्षीय संबंधों, विश्वास और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत किया।

पुरस्कार और सम्मान

- केरल में इनवेसिव पौधों की प्रजातियों का पता लगाने के लिए AI-पावर्ड ऐप बनाने के लिए बॉटनिस्ट एन. अलीम यूसुफ को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने सम्मानित किया । यह ऐप लगभग 100 प्रजातियों की पहचान करता है , बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में मदद करता है और इकोलॉजिकल खतरों का जल्दी पता लगाने में मदद करता है। मालाबार बॉटनिकल गार्डन और इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज में बनाया गया , यह रिसर्चर्स , फॉरेस्ट अधिकारियों और आम लोगों को मज़बूत बनाता है। यह इनोवेशन एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग , ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को दिखाता है । यह पहचान सस्टेनेबल डेवलपमेंट , क्लाइमेट एक्शन और दुनिया भर में इकोसिस्टम प्रोटेक्शन को मज़बूत करने की कोशिशों को दिखाता है।
- नई दिल्ली में हुए सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूज़िक अवॉर्ड्स 2026 में मशहूर कलाकारों सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्णराव पंडित को भारतीय क्लासिकल म्यूज़िक में उनके ज़िंदगी भर के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये अवॉर्ड्स बेहतरीन काम का जश्न मनाते हैं और युवा टैलेंट को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक विरासत को बचाने का मकसद रखते हैं। डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुए इस इवेंट में जाने-माने लोग आए और कैलाश खेर जैसे कलाकारों ने परफ़ॉर्म किया। कई शहरों में फैलते हुए, यह पहल पूरे भारत में पारंपरिक संगीत की ज़्यादा तारीफ़ को बढ़ावा देती है।
- भारतीय साइंटिस्ट परवीन शेख ने गंगा बेसिन में लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर को बचाने के लिए व्हिटली अवॉर्ड 2026 जीता है । उनके कम्युनिटी-लेड कंज़र्वेशन मॉडल , जिसमें लोकल "घोंसले के रखवाले" शामिल थे, ने पक्षियों के बचने की दर में सुधार किया और उनकी आबादी में काफ़ी बढ़ोतरी की। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सपोर्ट से, यह प्रोजेक्ट अब प्रयागराज तक फैलेगा , जो प्रदूषण और इंसानी दखल जैसी चुनौतियों का सामना करेगा। यह पहचान लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने में कम्युनिटी की भागीदारी, बायोडायवर्सिटी के बचाव और ज़मीनी स्तर पर पर्यावरण की कोशिशों के महत्व को दिखाती है।

खेल समाचार

- पंजाब किंग्स ने अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रन का पीछा करके इतिहास रच दिया , जो IPL इतिहास का सबसे बड़ा सफल चेज़ है । केएल राहुल ने शानदार 152 रन बनाए , जिसमें नीतीश राणा (91) का साथ मिला, जिससे DC 264 रन तक पहुंचा। जवाब में, प्रभसिमरन सिंह (76) और प्रियांश आर्य (73) ने PBKS को तेज़ शुरुआत दिलाई। कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम को जीत दिलाई। PBKS ने अपने पिछले 262 रन के रिकॉर्ड (2024) को भी पीछे छोड़ दिया , और IPL के टॉप चेज़ रिकॉर्ड्स में अपना दबदबा बनाया।
- सबेस्टियन सावे ने लंदन मैराथन 2026 में 1:59:30 में दौड़ पूरी करके इतिहास रच दिया , और ऑफिशियल सब-2-घंटे में मैराथन दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने केल्विन किप्टम का 2:00:35 का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया , और इंसानी सहनशक्ति को फिर से परिभाषित किया। योमिफ जैसे प्रतियोगी केजेल्चा और जैकब किप्लिमो ने भी रिकॉर्ड लेवल का प्रदर्शन किया। सावे की उपलब्धि की तुलना रोजर बैनिस्टर और उसैन बोल्ट जैसे दिग्गजों से की जाती है, जो एथलेटिक्स के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।
- काहिरा में हुए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत टॉप देश बना , उसने 16 मेडल (5 गोल्ड, 6 सिल्वर , 5 ब्रॉन्ज़) जीते, जिससे शूटिंग स्पोर्ट्स में उसकी बढ़ती ताकत का पता चला । हेमंत बर्मन ने 50m राइफल 3 पोजीशन इवेंट में सिल्वर मेडल जीता , जबकि ज़ुहैर खान और अद्या कत्याल ने ट्रैप मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता । महिलाओं के इवेंट्स में मिले-जुले नतीजों के बावजूद, भारत ने ओवरऑल दबदबा बनाया। अब फोकस जर्मनी में होने वाली ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पर है , जिससे ओलंपिक की तैयारी को बढ़ावा मिलेगा।

- विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच के दौरान हासिल की। अपने 275वें मैच में यह मुकाम हासिल करके कोहली ने सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले T20 बल्लेबाज के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वह IPL रन चार्ट में रोहित शर्मा और डेविड वॉर्नर जैसे खिलाड़ियों से आगे हैं। यह रिकॉर्ड फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक नया बेंचमार्क सेट करता है, जो उनके दबदबे, लंबे समय तक टिके रहने और लीग में उनके बेजोड़ योगदान को दिखाता है।
- पीवी सिंधु एथलीट्स कमीशन की चेयर बनीं और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल में वोटिंग रोल हासिल किया, जो ग्लोबल बैडमिंटन गवर्नेंस में एक ऐतिहासिक कदम है। एक एक्टिव एथलीट के तौर पर, वह खिलाड़ियों के हितों को रिप्रेजेंट करेंगी और सबसे ऊंचे लेवल पर पॉलिसी के फैसलों पर असर डालेंगी। उनका हिस्सा लेना एथलीट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच की दूरी को कम करता है, जिससे सबको साथ लेकर फैसले लेने की प्रक्रिया मजबूत होती है। BWF लीडरशिप के सपोर्ट से, यह कदम एथलीट रिप्रेजेंटेशन की अहमियत को दिखाता है और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस के भविष्य को बनाने में खिलाड़ियों की ज़्यादा भागीदारी के लिए एक मिसाल कायम करता है।
- तमिलनाडु की रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनीं, जो स्पोर्ट्स में सबको शामिल करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर एग्जाम में 'Other' कैटेगरी शुरू करने से, उनकी यह कामयाबी बढ़ते जेंडर रिप्रेजेंटेशन को दिखाती है। 2021 में अपना सफ़र शुरू करते हुए, उन्होंने सफल होने के लिए सामाजिक कलंक और रुकावटों को पार किया। उनकी पहचान भारत के 2014 के सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसजेंडर अधिकारों पर दिए गए फैसले से मेल खाती है, जो बराबरी और मौके को बढ़ावा देता है। यह अहम पल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स और गवर्नेंस में ट्रांसजेंडर लोगों की ज़्यादा भागीदारी को बढ़ावा देता है और उन्हें ज़्यादा अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
- पंजाब FC ने जिंक फुटबॉल अकादमी पर 3-0 की शानदार जीत के साथ AIFF एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब बरकरार रखा। पहले हाफ में कोई गोल नहीं होने के बाद, करिश सोरम, विशाल यादव और थोंग्राम ने गोल किए। ऋषिकांत सिंह ने जल्दी-जल्दी जीत पक्की कर दी। इस परफॉर्मेंस से पंजाब FC का युवाओं में दबदबा, ज़मीनी स्तर पर मज़बूत डेवलपमेंट और नेशनल कॉम्पिटिशन में लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखता है, जिससे वे इंडियन फुटबॉल में एक लीडिंग टैलेंट पाइपलाइन बन गए हैं।
- अपिया में कॉमनवेल्थ यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए चार गोल्ड मेडल जीते। सुनील सिंह, ऐसंगफा गोगोई, अभिनोब गोगोई और चारू पेसी जैसे एथलीटों ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क इवेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती है, जिसे मजबूत जमीनी स्तर की ट्रेनिंग, बेहतर कोचिंग और बढ़ती भागीदारी का सपोर्ट मिला है। यूथ और सीनियर कैटेगरी में सफलता एक अच्छे भविष्य का संकेत देती है और ग्लोबल खेल प्रतियोगिताओं में भारत की मौजूदगी को मजबूत करती है।
- भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने डेनमार्क के हॉर्सेंस में थॉमस कप 2026 में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया, सेमीफाइनल में जगह बनाई और मेडल पक्का किया —2022 के बाद यह उनका दूसरा आखिरी-चार का मैच था। लक्ष्य सेन ने चाउ टिएन- चेन पर वापसी करते हुए जीत हासिल की। डबल्स जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी – चिराग शेट्टी ने अपने मैच में दबदबा बनाया, जबकि डेब्यू कर रहे आयुष शेट्टी ने उलटफेर भरी जीत के साथ जीत पक्की कर दी। यह प्रदर्शन बैडमिंटन में भारत के बढ़ते दबदबे, मजबूत बेंच स्ट्रेंथ और दुनिया भर में बढ़ते कद को दिखाता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार

- स्काईरूट एयरोस्पेस ने विक्रम-1 के साथ एक बड़ी कामयाबी हासिल की। यह भारत का पहला प्राइवेट तौर पर बना ऑर्बिटल रॉकेट है, जिसे हैदराबाद से सतीश धवन स्पेस सेंटर ले जाया गया। ए. रेवंत रेड्डी ने इसे हरी झंडी दिखाई। यह मिशन प्राइवेट स्पेस सेक्टर की तरफ एक बदलाव का संकेत देता है। कम लागत वाले सैटेलाइट लॉन्च के लिए डिज़ाइन किया गया, विक्रम-1 लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) तक 350 kg ले जा सकता है और इसमें 3D-प्रिंटेड इंजन का इस्तेमाल होता है। IN- SPACe और ISRO के सपोर्ट से, यह पहल भारत की कमर्शियल स्पेस क्षमताओं और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देती है।
- देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप वाली महाराष्ट्र कैबिनेट ने 2031 तक ₹ 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने और 1.5 लाख नौकरियां बनाने के लिए AI पॉलिसी 2026 को मंज़ूरी दी। यह पॉलिसी AI इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग पर फोकस करती है, जिसमें AI इनोवेशन सिटीज़, GPU-बेस्ड कंप्यूटिंग और 2 लाख प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देना शामिल है। यह फंडिंग, सब्सिडी और इनक्यूबेटर के ज़रिए स्टार्टअप्स और MSMEs को सपोर्ट करती है। महा AI टूल्स हब जैसी पहलों के साथ, राज्य का लक्ष्य एक लीडिंग AI हब बनना है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ, रोज़गार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गगनयान को बढ़ाने की योजना बनाई है। अगले सिलेक्शन बैच में सिविलियन एस्ट्रोनॉट्स को शामिल करके प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। सिर्फ़ इंडियन एयर फ़ोर्स के टेस्ट पायलटों से आगे बढ़कर, इस पहल में STEM एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाएगा, जिससे भारत की ह्यूमन स्पेसफ़्लाइट क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। नए बैच में लगभग 10 कैंडिडेट्स शामिल हो सकते हैं, जो एडवांस्ड स्पेस रिसर्च और मिशन के लिए मिलिट्री और सिविलियन एक्सपर्टीज़ को मिलाएंगे। यह कदम स्पेस स्टेशन डेवलपमेंट और 2040 तक एक मानवयुक्त मून मिशन के भारत के लॉन्ग-टर्म विज़न के साथ मेल खाता है, जिससे ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसकी स्थिति मज़बूत होगी।

महत्वपूर्ण दिन समाचार

- 27 अप्रैल को मनाया जाने वाला वर्ल्ड डिज़ाइन डे 2026, आज की ज़िंदगी को बनाने में डिज़ाइन की अहमियत पर ज़ोर देता है। इसे इंटरनेशनल डिज़ाइन डे के नाम से भी जाना जाता है, यह इनोवेशन, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम-सॉल्विंग को बढ़ावा देता है। यह दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ़ डिज़ाइन (1963) की स्थापना की याद में मनाया जाता है और इसे पहली बार 1995 में मनाया गया था। डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाता है, जिससे ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर होती है और सस्टेनेबल सॉल्यूशन मुमकिन होते हैं। 50 से ज़्यादा देशों में मनाया जाने वाला यह दिन वर्कशॉप, एग्ज़िबिशन और सोशल मीडिया कैंपेन जैसी एक्टिविटीज़ में शामिल है, जो लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिज़ाइन की तारीफ़ करने और एक्टिव रूप से उससे जुड़ने के लिए बढ़ावा देता है।

- 28 अप्रैल को मनाया जाने वाला वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2026 , दुनिया भर में सुरक्षित और हेल्दी वर्कप्लेस को बढ़ावा देता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन के नेतृत्व में , यह एक्सीडेंट की रोकथाम , ऑक्यूपेशनल हेल्थ और वर्कर प्रोटेक्शन पर फोकस करता है । 2026 की थीम साइकोसोशल वेल-बीइंग पर ज़ोर देती है , जिसमें मेंटल हेल्थ , स्ट्रेस मैनेजमेंट और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट पर ज़ोर दिया जाता है। 2003 में शुरू हुआ यह दिन असुरक्षित हालात से प्रभावित वर्कर्स को भी सम्मान देता है। यह सरकारों , एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज को एक मज़बूत सेफ्टी कल्चर बनाने , मॉडर्न इकॉनमी में सम्मान , प्रोडक्टिविटी और इनक्लूसिव वर्कप्लेस पक्का करने के लिए बढ़ावा देता है।
- 29 अप्रैल को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस , सम्मान देता है जीन-जॉर्जेस नोवरे द्वारा शुरू किया गया और डांस को एक यूनिवर्सल भाषा के तौर पर बढ़ावा देता है। UNESCO के सपोर्ट से इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा ऑर्गनाइज़ किया गया यह दिन क्रिएटिविटी , कल्चरल एक्सचेंज और इमोशनल वेल-बीइंग पर ज़ोर देता है। यह सभी उम्र के लोगों को हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देता है, डांस को खुद को एक्सप्रेस करने , एजुकेशन और कल्चरल पहचान के एक टूल के तौर पर ज़ोर देता है । दुनिया भर में मनाया जाने वाला यह दिन एकता को बढ़ावा देता है , आर्टिस्टिक आज़ादी को सपोर्ट करता है , और एजुकेशन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डांस को शामिल करने के बारे में अवेयरनेस बढ़ाता है।
- इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई, 2026 को वर्कर्स को सम्मान देने और लेबर राइट्स, सही सैलरी और सुरक्षित काम करने के हालात को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है । हेमार्केट अफेयर से शुरू हुआ यह दिन दुनिया भर के लेबर मूवमेंट का प्रतीक है । भारत में, इसे सबसे पहले 1923 में सिंगारवेलु चेट्टियार ने मनाया था, इसमें रैलियां और अवेयरनेस कैंपेन शामिल हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन की 2026 की थीम साइकोसोशल वर्कप्लेस हेल्थ पर फोकस करती है , जिसमें स्ट्रेस और वर्क-लाइफ बैलेंस को एड्रेस किया जाता है। यह दिन सोशल जस्टिस, वर्कर डिग्निटी और लेबर लॉ रिफॉर्म्स पर ज़ोर देता है , जो नेशनल डेवलपमेंट में वर्कफोर्स के रोल पर ज़ोर देता है।
- गुजरात स्थापना दिवस 1 मई, 2026 को मनाया जाता है , जो बॉम्बे रीऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट के तहत बॉम्बे स्टेट से अलग होने के बाद 1960 में गुजरात के बनने की याद में मनाया जाता है। राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व इंदुलाल याग्निक ने किया था। 2026 में, सूरत में बड़े समारोह होते हैं , जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुलिस बाइक स्टंट होते हैं। यह दिन गुजरात की सांस्कृतिक विरासत, एकता और आर्थिक तरक्की को दिखाता है , और भारत के उद्योग, व्यापार और विकास में एक बड़े योगदानकर्ता के रूप में इसकी भूमिका का जश्न मनाता है।
- महाराष्ट्र दिवस 1 मई, 2026 को मनाया जाता है , जो 1960 में बॉम्बे राज्य के महाराष्ट्र और गुजरात में बंटवारे के बाद महाराष्ट्र बनने की याद में मनाया जाता है। राज्य की मांग का नेतृत्व संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन ने किया था , जो मराठी बोलने वाले लोगों की एकता और पहचान को दिखाता है। यह दिन आंदोलन के दौरान दिए गए बलिदानों का सम्मान करता है और सांस्कृतिक गौरव, भाषा और विरासत का जश्न मनाता है। झंडा फहराने, शिवाजी पार्क में परेड और लावणी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाने वाला यह दिन भारत में एक प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक राज्य के रूप में महाराष्ट्र के सफर को दिखाता है।

शोक समाचार

- मशहूर भारतीय फोटो जर्नलिस्ट रघु राय का 83 साल की उम्र में निधन हो गया , जिससे भारतीय फोटोग्राफी में एक युग का अंत हो गया। भारत की सामाजिक , राजनीतिक और सांस्कृतिक यात्रा को डॉक्यूमेंट करने के लिए जाने जाने वाले , उन्होंने अपने निधन से पहले कैंसर से लड़ाई लड़ी थी। 1965 में अपना करियर शुरू करने के बाद, हेनरी कार्टियर-ब्रेसन से मेंटरशिप मिलने और मैग्नम फोटोज से जुड़ने के बाद उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। उनके मशहूर काम में 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध , शरणार्थी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी शामिल थी। पद्म श्री पाने वाले , उन्होंने इंडिया टुडे के साथ भी काम किया, और भारत में मॉडर्न फोटो जर्नलिज्म को आकार दिया।
- जाने-माने एक्टर-डायरेक्टर भरत कपूर का 80 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। वे इंडियन सिनेमा में एक अमीर विरासत छोड़ गए। 1972 में अपने करियर की शुरुआत करते हुए , उन्होंने 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें नूरी और खुदा गवाह जैसी फिल्मों में अलग-अलग तरह के रोल के लिए जाना जाता है। उन्होंने तारा और अमानत जैसे टेलीविज़न सीरियल से भी लोकप्रियता हासिल की। एक डायरेक्टर के तौर पर, उन्होंने रईसज़ादा जैसी फिल्में बनाईं। मज़बूत सपोर्टिंग रोल और किरदारों की गहराई के लिए मशहूर , कपूर ने फिल्मों और टीवी दोनों में अहम योगदान दिया, कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारत की सिनेमाई विरासत को बेहतर बनाया।

स्टेटिक टेकअवे

पहलू	विवरण
आंध्र प्रदेश	राज्यपाल: अब्दुल नज़ीर मुख्यमंत्री: चंद्रबाबू नायडू राजधानी: अमरावती
गुजरात	राज्यपाल: आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री: भूपेंद्र पटेल राजधानी: गांधीनगर
महाराष्ट्र	राज्यपाल: जिष्णु देव वर्मा मुख्यमंत्री: देवेंद्र फडणवीस राजधानी: मुंबई
पश्चिम बंगाल	राज्यपाल: आरएन रवि मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी राजधानी: कोलकाता
उतार प्रदेश।	राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ राजधानी: लखनऊ
नीति आयोग	अध्यक्ष: ओम नरेंद्र मोदी
पंचायती राज मंत्री	ललन सिंह
रक्षा मंत्री	राजनाथ सिंह

Adda247 LIVE CLASSES

Online LIVE Classes for SSC, Banking, Railways and Other Govt Exams

Live & Recorded Classes

PDF Notes & Study Material

Mock Tests & Practice Questions

Doubt Solving Sessions

- Expert Faculty with Interactive Classes
- Full Exam Syllabus Coverage + Mock Tests
- Courses Available in Hindi, English & Regional Languages

Get Started Now

पहलू	विवरण
वित्त मंत्री	निर्मला सीतारमण
गृह मंत्री	अमित शाह
एमएसएमई मंत्री	जीतन राम मांझी
संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री	अश्विनी वैष्णव
कर्नाटक	राज्यपाल: थावर चंद गहलोत मुख्यमंत्री: सिद्धारमैया राजधानी: बेंगलुरू
संयुक्त अरब अमीरात	राष्ट्राध्यक्ष: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान राजधानी: अबू धाबी
फिनलैंड	राष्ट्रपति: अलेक्जेंडर स्टब राजधानी: हेलसिंकी
भारतीय रिजर्व बैंक	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा
कौन	राष्ट्रपति: डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस
संयुक्त राष्ट्र महासभा	अध्यक्ष: एनालेना बैरबॉक
सेबी	अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे
इसरो	अध्यक्ष: वी. नारायणन
डेनमार्क	PM: मेटे फ्रेडरिक्सन राजधानी: कोपेनहेगन